

न्यायालय जिला कलेक्टर, सिरौही (राज.)
बईजलस श्रीमती अल्पा चौधरी, आई.ए.एस.

प्रार्थी

पंचायत निगरानी सं. 93/2024

विकास अधिकारी पंचायत समिति पिण्डवाडा जिला सिरौही।

बनाम

अप्रार्थीगण

1. सरपंच ग्राम पंचायत रोहिडा तहसील पिण्डवाडा जिला सिरौही।
2. श्री प्रदीप कुमार पुत्र श्री बच्चूलाल जाति जैन निवासी रोहिडा तहसील पिण्डवाडा जिला सिरौही।

पंचायत निगरानी प्रार्थना-पत्र अन्तर्गत धारा 97 राज. पंचायती
राज अधिनियम, 1994

उपरिस्थिति :-

1. श्री नटवरलाल जीनगर सहायक विकास अधिकारी जिला परिषद सिरौही प्रार्थी की ओर से।
2. अधिवक्ता श्री राजेन्द्रसिंह आढा, अप्रार्थी संख्या दो की ओर से।

निर्णय

दिनांक 27.03.2025

संक्षेप में प्रकरण के तथ्य इस प्रकार हैं कि प्रार्थी ने यह निगरानी प्रार्थना-पत्र राजस्थान पंचायती राज अधिनियम 1994 की धारा 97 के तहत प्रस्ताव संख्या 12 दिनांक 05.07.2019 की पालना में राजस्थान पंचायतीराज नियम 1996 के नियम 157(1) के तहत सरपंच ग्राम पंचायत रोहिडा द्वारा अप्रार्थी संख्या दो के हक में जारी पट्टा संख्या 88 दिनांक 21.08.2019 क्षेत्रफल 450.10 वर्गफीट को निरस्त कराने हेतु प्रस्तुत किया। प्रार्थी का प्रार्थना-पत्र दर्ज रजिस्टर किया जाकर अप्रार्थी को नोटिस जारी किये गये। अप्रार्थी संख्या दो की ओर से अधिवक्ता श्री राजेन्द्रसिंह आढा द्वारा वकालतनामा पेश कर उपरिस्थिति दी एवं जवाब प्रस्तुत किया, जो शामिल मिसल किया गया। अतः प्रकरण में दोनों पक्षों की विस्तृत बहस सुनी गई।

प्रार्थी की ओर से श्री नटवरलाल जीनगर सहायक विकास अधिकारी जिला परिषद सिरौही ने दौराने बहस मेरा ध्यान प्रार्थी की ओर से प्रस्तुत प्रार्थना-पत्र में अंकित तथ्यों की ओर आकर्षित करते हुए यह व्यक्त किया कि ग्राम पंचायत रोहिडा द्वारा दिनांक 05.07.2019 को लिए गए प्रस्ताव संख्या 12 को ग्राम विकास अधिकारी के द्वारा अपने स्व-विवेक से अंकित किया गया है, जबकि पंचायत नियम 48 के उपनियम 6 के अनुसार प्रत्येक बैठक कार्यवाही रजिस्टर में बैठक कार्यवाही विचार विमर्श के बाद अभिलिखित की जाएगी और अध्यक्षता करने वाला प्राधिकारी पढकर सुना दिए जाने के बाद हस्ताक्षरित की जाएगी, जिससे उक्त विक्रय विलेख स्वविवेक से प्रस्ताव पारित कर जारी करने से निरस्त योग्य है। यह कि अप्रार्थी संख्या एक ने अप्रार्थी संख्या दो को जारी विक्रय विलेख की मिसल पत्रावली का अवलोकन पर पाया गया कि नक्शा फॉर्म पर नक्शा नवीस के हस्ताक्षर का अभाव, गौका निरीक्षक रिपोर्ट पर दो पंचों के हस्ताक्षर का अभाव एवं आपत्ति इशतहार चरपा किए जाने का अभाव पाया गया। इस प्रकार अप्रार्थी संख्या एक ने अप्रार्थी

के.ए.
जिला कलेक्टर, सिरौही

संख्या दो को अनुचित लाभ देने के लिए नियम विरुद्ध विक्रय विलेख जारी किया गया है, जो निरस्त किए जाने योग्य है। यह कि अप्रार्थी संख्या एक ने अप्रार्थी संख्या दो के पक्ष में राजस्थान पंचायतीराज के नियम 145 से 149 की पूर्ण अवहेलना करते हुए अवैधानिक तरीक के विक्रय विलेख जारी किए गए हैं। शिकायत प्रस्तुत होने पर जांच के आधार पर ही निगरानी प्रार्थना पत्र पेश किया गया है। पंचायत द्वारा नियमों की अवहेलना कर प्रस्ताव पारित किया गया है। अतः श्रीमान से निवेदन है कि प्रार्थी का प्रार्थना पत्र स्वीकार फरमाकर सरपंच ग्राम पंचायत रोहिडा द्वारा अप्रार्थी संख्या दो के हक में जारी पट्टा संख्या 88 दिनांक 21.08.2019 क्षेत्रफल 450.10 वर्गफीट को निरस्त करना फरमावें।

अप्रार्थी संख्या दो के लायक अधिवक्ता श्री राजेन्द्रसिंह आढ़ा द्वारा दौराने बहस मेरा ध्यान निगरानी में प्रस्तुत जवाब में अंकित तथ्यों की ओर आकर्षित करते हुए निवेदन किया कि पंचायत द्वारा अप्रार्थी संख्या दो को नियम 157(1) के तहत पुराने मकान का पट्टा जारी करने का प्रस्ताव पारित करने में कोई अनियमितता अथवा नियमों का उल्लंघन नहीं किया है। ग्राम पंचायत रोहिडा को आवादी भूमि में विक्रय विलेख जारी करने का अधिकार होने से उक्त प्रस्ताव विधि अनुसार पारित किया गया है। यह है कि प्रार्थी की ओर से प्रस्तुत निगरानी प्रार्थना पत्र के साथ संलग्न ग्राम पंचायत रोहिडा द्वारा जारी पट्टे की सूची के क्रम संख्या 37 पर अप्रार्थी संख्या दो का नाम दर्ज है, जिसके आगे उल्लेख किया गया है जिसमें मौके पर मकान नहीं हो, ऐसा कोई कथन उल्लेख नहीं किया गया है। केवल ग्राम पंचायत में उपलब्ध नक्शा फॉर्म पर नक्शा नवीस के हस्ताक्षर का अभाव, मौका निरीक्षण रिपोर्ट पर दो पंचों के हस्ताक्षर आपत्ति ईशितहार चस्या किये जाने का अभाव का उल्लेख किया है। उक्त पत्रावली में पुराना आवास का नजरी नक्शा पेश किया हुआ है। पट्टा जारी करने से पूर्व आपत्ति नोटिस जारी करने का उल्लेख किया हुआ है तथा अप्रार्थी संख्या दो व अन्य गवाहान के शपथ पत्र प्रस्तुत किये हुये हैं तथा मौका निरीक्षण नक्शा शुल्क तथा पट्टा बनाने के आवेदन शुल्क भी अप्रार्थी संख्या दो द्वारा जमा करवाया हुआ है। इस प्रकार अप्रार्थी संख्या दो की ओर से सम्पूर्ण औपचारिकता पूर्ण की गयी है तथा ग्राम पंचायत द्वारा भी सम्पूर्ण औपचारिकता पूर्ण कर नियमानुसार पट्टा जारी किया गया है। कार्यवाही रजिस्टर में बैठक का संधारण करना ग्राम पंचायत में ग्राम विकास अधिकारी का कर्तव्य निर्वहन में आता है, जिन्होंने भी नियमानुसार बैठक की कार्यवाही रजिस्टर में संधारित की है। अधिक पट्टे एक साथ जारी करते समय अगर मिसल में कोई त्रुटि सहवन से रह भी गई है तो उससे उक्त पट्टा अवैध नहीं होता है। उक्त त्रुटि को कभी भी दुरुस्त किया जा सकता है। इस प्रकार प्रार्थी की ओर से उक्त निगरानी प्रार्थना पत्र गलत कथनों के आधार पर पेश किया गया है। यह कि ग्राम पंचायत द्वारा अप्रार्थी संख्या दो के हक में पट्टा जारी करने के पश्चात् उक्त पट्टे को उपपंजीयक कार्यालय में पंजीयन करवाया गया है। इस प्रकार उक्त पट्टा एक पंजीयनशुदा दस्तावेज है, जिसको सक्षम सिविल न्यायालय द्वारा ही निरस्त करवाया जा सकता है। प्रार्थी ने इस संबंध में सिविल न्यायालय में उक्त पट्टे को चुनौती नहीं दी है जिसके अभाव में यह प्रार्थना पत्र कानूनन परिपोषणीय नहीं है। यह कि अप्रार्थी संख्या दो का पुश्तैनी आवासीय मकान बना हुआ है जिसका नियमानुसार पात्रता रखने से ही अप्रार्थी संख्या दो से नियमानुसार शुल्क प्राप्त कर पट्टा जारी किया गया है जिसमें राज्य सरकार या ग्राम पंचायत को किसी प्रकार से कोई आर्थिक क्षति नहीं हुई है। यह कि प्रार्थी की ओर से निगरानी प्रार्थना पत्र के साथ शपथ पत्र प्रस्तुत नहीं किया है न ही प्रार्थना पत्र को प्रमाणित किया है जिसके अभाव में यह प्रार्थना पत्र कानूनन परिपोषणीय नहीं है। अतः श्रीमान से नम्र निवेदन है कि प्रार्थी द्वारा प्रस्तुत उक्त निगरानी प्रार्थना पत्र विरुद्ध अप्रार्थी संख्या दो मय खर्चे हर्जे खारिज कराना फरमावे व अप्रार्थी को प्रार्थी से विशेष हर्जाना के रूपये 10,000/- दिलाना फरमावे।

उभय पक्ष की सुनी गई बहस पर मनन किया। प्रार्थी की ओर से प्रस्तुत प्रार्थना-पत्र एवं अप्रार्थी संख्या दो की ओर से प्रस्तुत जवाब एवं पत्रावली का भलिभाँति नियमों के परिप्रेक्ष्य में अध्ययन एवं अवलोकन किया गया तो निष्कर्ष निम्न प्रकार है :-

जिला कलेक्टर, विरोही

अप्रार्थी संख्या दो को उक्त पट्टा संख्या 88 दिनांक 21.08.2019 क्षेत्रफल 450.10 वर्गफीट सरपंच ग्राम पंचायत, रोहिडा द्वारा राजस्थान पंचायती राज सामान्य नियम 1996 के नियम 157(1) के तहत जारी किया गया है। राजस्थान पंचायती राज सामान्य नियम 1996 के नियम 157(1) के अनुसार-

157.-पुराने गृहों का विनियमितकरण- जहाँ व्यक्ति आवादी भूमि में पुराने गृह का कब्जा रखते हैं और पट्टा जारी कराने के इच्छुक वहाँ उन्हें निम्नलिखित प्रमार निक्षिप्त कराने के पश्चात् प्ररूप 23 क में पंचायत द्वारा पट्टा जारी किया जा सकेगा-

1. 300 वर्गगज तक के क्षेत्रफल के लिए या 300 वर्गगज अधिकतम क्षेत्रफल के अध्यक्षीन रहते हुए 25 प्रतिशत सनिर्मित क्षेत्रफल को सम्मिलित करते हुए सनिर्मित क्षेत्रफल:

क. इन नियमों के प्रारम्भ की तारीख से पूर्व, पचास वर्षों से अधिक पूर्व में = 100 रुपये सनिर्मित पुराने गृहों के लिए।

ख. (31 दिसम्बर 2016 के ठीक पूर्ववर्ती सत्तर वर्षों के दौरान) = 200 रुपये सनिर्मित पुराने गृहों के लिए।

पत्रावली पर उपलब्ध दस्तावेजी साक्ष्यों के अवलोकन से यह प्रतीत होता है कि ग्राम पंचायत रोहिडा द्वारा दिनांक 05.07.2019 को प्रस्ताव संख्या 12 पारित किया गया, जिसकी पालना में अप्रार्थी संख्या दो को राजस्थान पंचायतीराज नियम 1996 के नियम 157 उपनियम (1) के अन्तर्गत विक्रय विलेख जारी किया गया था। पत्रावली पर उपलब्ध दस्तावेजी साक्ष्यों के अवलोकन से यह प्रतीत होता है कि ग्राम पंचायत रोहिडा द्वारा दिनांक 05.07.2019 को ग्राम पंचायत की साधारण बैठक सरपंच ग्राम पंचायत रोहिडा की अध्यक्षता में आयोजित की, जिसमें प्रस्ताव संख्या 01 से 12 पारित किए गए, परन्तु ग्राम पंचायत रोहिडा की बैठक कार्यवाही रजिस्टर की प्रमाणित प्रति का अवलोकन करने पर यह प्रतीत होता है कि ग्राम पंचायत रोहिडा की उक्त बैठक में प्रस्ताव पारित करने से पूर्व ही उपस्थित पंचायत सदस्यों से हस्ताक्षर करवा लिए गए थे, जबकि ग्राम पंचायत की बैठक में कौम की गणना के लिए बैठक से पूर्व हस्ताक्षर कराने का कोई प्रावधान नहीं है एवं राजस्थान पंचायती राज अधिनियम 1994 की धारा 48(6) में भी यह स्पष्ट प्रावधान है कि पंचायतीराज संस्थाओं की बैठक कार्यवाही कार्यवृत्त पुस्तक में विचार-विमर्श के ठीक पश्चात अभिलिखित की जाएगी और बैठक की अध्यक्षता करने वाले प्राधिकारी द्वारा पढकर सुना दिए जाने के पश्चात उसके द्वारा हस्ताक्षरित की जाएगी। ग्राम पंचायत रोहिडा द्वारा दिनांक 05.07.2019 को सम्पन्न हुई बैठक रजिस्टर का अवलोकन करने पर यह प्रतीत होता है कि प्रस्ताव संख्या 12 को पारित करने के पश्चात बैठक में उपस्थित अध्यक्ष एवं किसी भी पंचायत सदस्य के हस्ताक्षर नहीं है, जबकि राजस्थान सरकार ग्रामीण विकास एवं पंचायती राज विभाग के पत्र क्रमांक:-एफ.40(49)15वीं/सत्र-4/ध्याना.प्रस्ताव/परावि/2020/87 दिनांक 02.02.2021 के द्वारा यह स्पष्ट किया गया है कि पंचायतीराज संस्थाओं की समस्त बैठकों के कार्यवाही विवरण रजिस्टर में कार्यवाही विवरण अंकन के पश्चात् रेखा खींची जाए एवं जहाँ विवरण समाप्त हो, वहीं सम्बन्धित समस्त जनप्रतिनिधिगण एवं सचिव अर्थात् ग्राम सेवक, विकास अधिकारी तथा मुख्य कार्यकारी अधिकारी के हस्ताक्षर करवाए जाए। अतः इससे यह स्पष्ट होता है कि ग्राम पंचायत रोहिडा द्वारा दिनांक 05.07.2019 को पारित किया गया प्रस्ताव संख्या 12 ग्राम पंचायत की बैठक के अध्यक्ष एवं पंचायत सदस्यों की उपस्थिति में पारित नहीं किया गया है, जो उचित प्रतीत नहीं होता है। यहाँ यह भी उल्लेखनीय है कि उक्त प्रस्ताव संख्या 12 दिनांक 05.07.2019 के अवलोकन से यह प्रतीत होता है कि क्रम संख्या 01 से 41 तक अंकित व्यक्तियों के नाम लगातार लिखने के बाद क्रम संख्या 42 से 53 पर अंकित व्यक्तियों के नाम अगले पृष्ठ पर लिखा जाना चाहिए था, परन्तु क्रम संख्या 42 से 53 पर अंकित व्यक्तियों के नाम अगले पृष्ठ पर अंकित नहीं कर क्रम संख्या 01 से 12 के सामने अंकित किए गए हैं, जिससे यह प्रतीत होता है कि क्रम संख्या 01 से 41 तक व्यक्तियों के नाम उक्त प्रस्ताव संख्या 12 में लिखने के बाद में क्रम संख्या 42 से 53 तक अंकित व्यक्तियों के नाम इस प्रस्ताव में जोड़े गए हैं, जिससे इस प्रस्ताव को पारित करने की

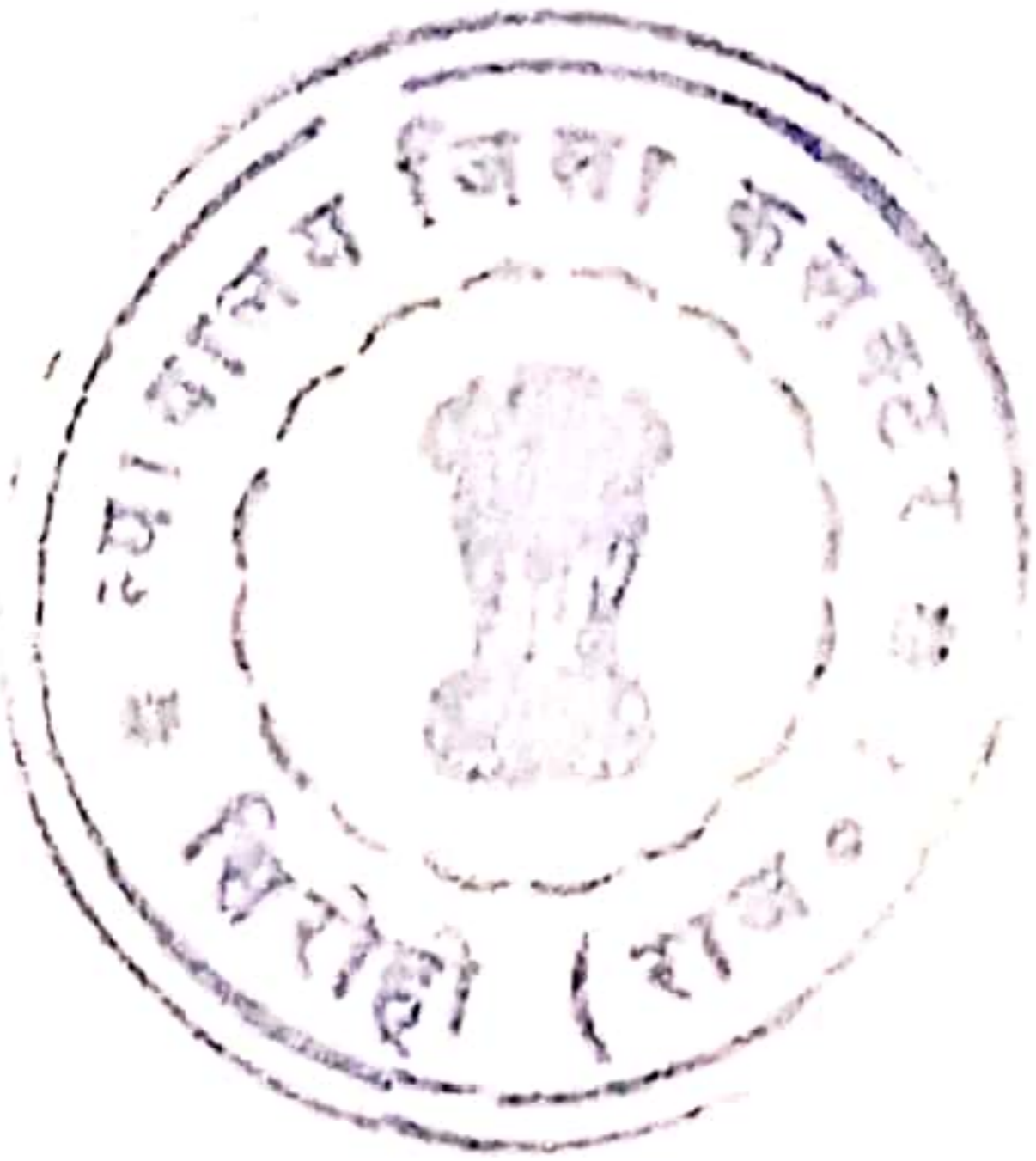


जिला कलेक्टर, चिरोही

कार्यवाही संदेहारपद प्रतीत होती है। चूंकि अप्रार्थी संख्या दो द्वारा ग्राम पंचायत में पट्टा प्राप्त करने हेतु आवेदन प्रस्तुत करने के बाद की समस्त कार्यवाही ग्राम पंचायत के स्तर पर ही सम्पन्न की गई है, जिससे उक्त वादग्रस्त पट्टे के सम्बन्ध में लिया गया विधि विरुद्ध प्रस्ताव संख्या 12 भी ग्राम पंचायत के स्तर पर ही की गई भूल कारित किया जाना पाया जाता है। इसके अलावा नक्शा फॉर्म पर नक्शा नवीस के हस्ताक्षर का अभाव एवं आपत्ति इशतहार चरपा किए जाने का अभाव एवं पट्टे पर सचिव के हस्ताक्षर का अभाव पाया जाना भी ग्राम पंचायत के स्तर पर ही की गई गलती है, जिसके लिए अप्रार्थी संख्या दो को उत्तरदायी ठहराया जाना उचित प्रतीत नहीं होता है।

अतः उपरोक्त विवेचन एवं पत्रावली पर उपलब्ध दस्तावेजी साक्ष्यों के अवलोकन से प्रार्थी का निगरानी प्रार्थना पत्र आंशिक रूप से स्वीकार किया जाकर ग्राम पंचायत रोहिडा द्वारा पारित प्रस्ताव संख्या 12 दिनांक 05.07.2019 की पालना में राजस्थान पंचायतीराज नियम 1996 के नियम 157(1) के तहत अप्रार्थी संख्या दो के हक में जारी पट्टा संख्या 88 दिनांक 21.08.2019 क्षेत्रफल 450.10 वर्गफीट को निरस्त किया जाता है। साथ ही सरपंच/ग्राम विकास अधिकारी ग्राम पंचायत रोहिडा को निर्देशित किया जाता है कि अप्रार्थी संख्या दो द्वारा पूर्व में दिए गए आवेदन के सम्बन्ध में उक्त भूखण्ड की मौके पर कब्जे व मालिकी स्वामित्व की जांच कर एवं राजस्थान पंचायतीराज नियम 1996 में प्रदत्त प्रावधानों के अनुसार जांच कर नियमानुसार नए सिरे से दो माह के अन्दर पट्टा जारी करें और अप्रार्थी संख्या दो के पास ग्राम पंचायत रोहिडा में जमा करवाए गए शुल्क की मूल रसीद है, तो उनका उतना शुल्क जमा माना जावे।

निर्णय आज दिनांक 27.03.2025 को खुले न्यायालय में डिक्टेट कराया जाकर सरे इजलास सुनाया गया।



(Handwritten Signature)
(अल्पा चौधरी)
जिला कलक्टर, सिरोही